सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) छत्तीसगढ़

17

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) छत्तीसगढ़

मुख्य बिन्दु

- संयुक्त राष्ट्र (United Nations) और उसके सदस्य देशो ने अक्टूबर 2015 में विश्व में सभी के लिए, समानता, मानवाधिकार और न्याय को बढ़ावा देने के लिए, सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals & SDG) को अपनाया। इसमें 17 लक्ष्य/उद्दश्यों (Goals) में 169 वैश्विक टारगेट (Targets) शामिल हैं।

- SDG इंडिया इंडेक्स 3-0 सूचकांक का नवीनतम संस्करण है जिसे 2021 में लॉन्च किया गया है। इसका गणना 109 संकेतकों का उपयोग करके किया गया है।

- SDG इंडिया इंडेक्स–2021 में छत्तीसगढ़ का समग्र स्कोर 61 अंक था और वें 28 राज्य में 19वें स्थान पर था। छत्तीसगढ़ का स्थान परफॉर्मर श्रेणी में था और SDG लक्ष्य–5 में शीर्ष स्थान पर था।

- छत्तीसगढ़ –एसआईएफ में 17 सतत विकास लक्ष्य मे 16 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी लक्ष्य–14 को छोड़कर) के प्रगति को मापने के लिए कुल 275 संकेतक शामिल हैं।

- सीजी–डीआईएफ में 15 एसडीजी (लक्ष्य 14 और लक्ष्य 17 को छोड़कर) के लिए 82 संकेतिक शामिल हैं।

- जिला स्तरीय एसडीजी रिपोर्ट (2022) में छत्तीसगढ़ कम्पोजिट एसडीजी स्कोर 2021–2022 के दौरान 4 अंक बढ़कर 64 से 68 हो गया।

- धमतरी SDG मे छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले है, और इस वर्ष 77 के SDG स्कोर के साथ दोनों वर्षों (2021 & 2022) में शीर्ष पर रहा।

17.1 पृष्ठभूमि

'सतत विकास' एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधानो की निरंतरता के उपर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना है। इसमें पर्यावरण की रक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के साथ–साथ आर्थिक वृद्धि और विकास हासिल करने के तरीके खोजना शामिल है। सतत विकास शब्द 1987 में संयुक्त राष्ट्र की **"Our Common future"** रिपोर्ट में गढ़ा गया था, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है।

पूर्व में सतत विकास की पारंपरिक धारा मे तीन प्रमुख तत्वोः आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश, और पर्यावरण संरक्षण के आधार पर अवलोकन किया जाता था, वर्तमान मे सतत विकास की अवधारणा में दो और महत्वपूर्ण तत्वोः भागीदारी और शांति को जोड़ा गया है।

चित्र–1: सतत विकास के 5 आयाम

सतत विकास लक्ष्य बर्ष 2030 तक और अधिक न्याय संगत, शांतिपूर्ण, लचीले और समृद्ध समुदायो की ओर बढ़ने हेतु एक विकास की अवधारणा है। जो दुनिया के सभी लोगों के लिए वर्तमान और भविष्य में शांति, समृद्धि, और विकास दिशा मे एक साझा रणनीति प्रदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र **(United Nations)** और उसके सदस्य देशो ने अक्टूबर 2015 में विश्व में सभी के लिए समानता, मानवाधिकार और न्याय को बढ़ावा देने के लिए, सतत विकास लक्ष्यों **(Sustainable Development Goals-SDG)** को अपनाया। इसमे **17 लक्ष्य/उद्देश्यो (Goals)** में **169 वैश्विक टारगेट (Targets)** शामिल हैं।

सतत विकास के 17 उद्देश्यो के बेहतर आंकलन के प्रायोजन हेतु 5 महत्वपूर्ण आयामो में वर्गीकृत किया गया है: लोग **(People)**, धरती **(Planet)**, समृद्धि **(Prosperity)**, शांति **(Peace)**, साझेदारी **(Partnership)** है, जिन्हे 5 पीज (OPs) के नाम से भी जाना जाता है।

चित्र–2: सतत विकास के 5Ps

Image Source: SPSP (2024), UNICEF-Raipur, Chhattisgarh

संयुक्त राष्ट्र एसडीजी दिशा निर्देश- के तहत देशो से इन लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए इन्हे अंगीकार करने तथा एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क स्थापित करने की अपेक्षा की गयी है। इनका कार्यान्वयन एवं सफलता राष्ट्रो की अपनी सतत विकास नीतियो, योजनाओ एवं कार्यक्रमो पर निर्भर करेगी। एजेंडा 2030 द्वारा इस तथ्य को भी रेखांकित किया गया है की टार्गेट्स पर हुई प्रगती को मापने तथा इसके मुख्य व परिवर्तनकारी संकल्प यथा

''कोई भी पीछे ना रहे'' को सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण, विस्वसवानीय एवं बिसमुहित इंडिकेटर्स एवं उससे सम्बंधित आँकड़ो की आबश्यकता होगी।

संयुक्त राष्ट्र एसडीजी दिशानिर्देश

एसडीजी मे बर्ष 2030 तक सभी रूपों और आयामों में बिश्व मे गरीबी को समाप्त करने की एक साहसिक प्रतिबद्धता है। इसमें सबसे कमजोर लोगों को चिन्हित करके ग़रीबी रेखा से उपर लाना, समस्त पुरुष ,बच्चो, महिलाए और बुज़ुर्गो को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना ,बुनियादी संसाधनों और सेवाओं को बढ़ाना और जलवायु-संबंधी आपदाओं से प्रभावित समुदायों का समर्थन करना शामिल है।

- दुनिया भर मे देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे एसडीजी प्रक्रिया की स्वामित्व लें और 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करें।
- सभी हितधारकों: सरकारों, नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) आदि से इस एजेंडे को साकार करने में योगदान देने की अपेक्षा की गयी है।
- सरकारों को लक्ष्यों और वैश्विक टारगेट पर हुई प्रगति की निगरानी में सहायता के लिए अपने स्वयं के राष्ट्रीय संकेतक विकसित करने की अपेक्षा की गयी है।
- एसडीजी के कार्यान्वयन और सफलता हेतु देशों को अपनी सतत विकास नीति, योजनाए और कार्यक्रम समूह तैयार करने की अपेक्षा की गयी है।
- 2030 तक एसडीजी लक्ष्यों और वैश्विक टारगेट में हुई प्रगति के संबंध में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई और समय समय पर समीक्षा करना हर देश की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
- एसडीजी लक्ष्यों और वैश्विक टारगेट में हुई प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाइयों के लिए गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समय पर डेटा संग्रह और क्षेत्रीय अनुवर्ती और समीक्षा की आवश्यकता भी है।

दुनिया के राष्ट्रध्यक्षों ने सितम्बर, 2019 मे आयोजित एस. डी. जी. के शिखर सम्मेलन मे सतत विकास उद्देश्यो को प्राप्त करने मे शेष रही 10 बर्ष से भी कम अवधि को "कार्रवाई का दशक" (Decade of Actions) के रूप मे घोषित किया गया है और सतत विकास उद्देश्यो को वर्ष बढ़ाने 2030 तक प्राप्त करने हेतु वित्तीय संसाधनो को संचालित करने, राष्ट्रीय क्रियान्वयन को बड़ाने तथा संस्थानो को मजबूत करने हेतु कहा है। सितंबर 2019 में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने समाज के सभी क्षेत्रों से तीन स्तरों पर एक दशक की कार्रवाई के लिए जुटने का आह्वान किया।

- सतत विकास लक्ष्यों के लिए अधिक नेतृत्व, अधिक संसाधन और बेहतर समाधान सुरक्षित करने के लिए वैश्विक कार्रवाई (Global Actions)
- सरकारों, शहरों और स्थानीय अधिकारियों की नीतियों, बजट, संस्थानों और नियामक ढांचे में आवश्यक बदलावों को शामिल करने वाली स्थानीय कार्रवाई (Local Actions)

- और आवश्यक परिवर्तनों के लिए एक अजेय आंदोलन उत्पन्न करने के लिए युवाओं, नागरिक समाज, मीडिया, निजी क्षेत्र, यूनियनों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों सहित लोगों की कार्रवाई (People Actions)

चित्र–3: एसडीजी के संक्षिप्त इतिहास

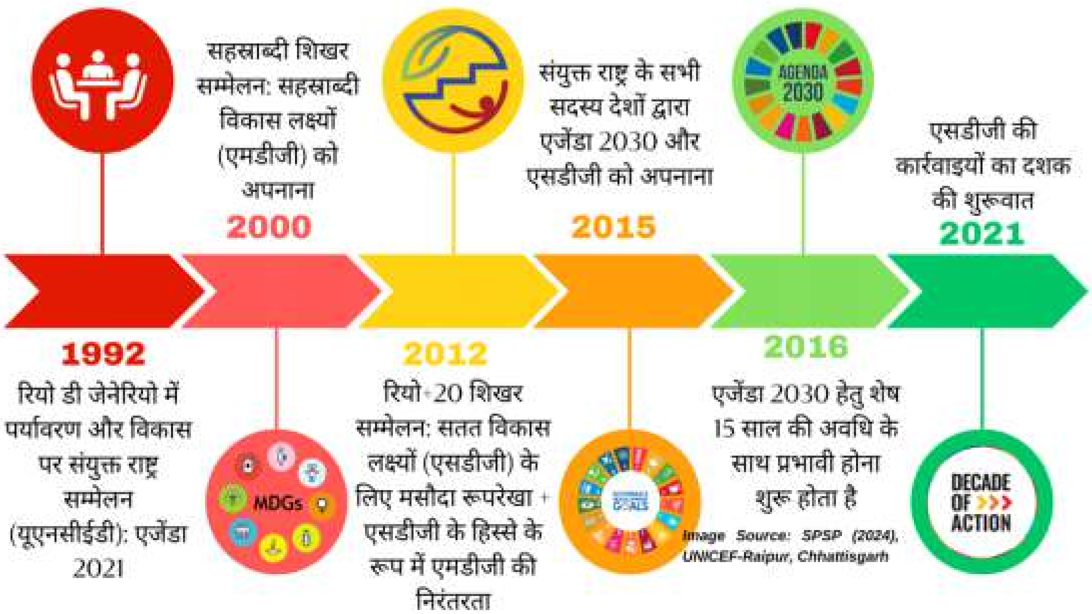

17.2 सतत विकास लक्ष्य

लक्ष्य–1: गरीबी का अंत- एस. डी.जी.–1 का केन्द्रीय विषय गरीबी का अंत करना है। गरीबी एक बहुआयामी स्थिति है जो न केवल आय की कमी या संसाधनो तक पहुँच को इंगित करती हैं जबकि भुखमरी व कुपोषण, संकुचित अवसरो, सामाजिक भेदभाव तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थता के रूपों में भी प्रकट होती है। गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करना मानवजाति के लिये विकट चुनौतियों में से एक है।

लक्ष्य–2: भुखमरी समाप्त करना- एस.डी.जी.–2 का उद्देश्य सभी लोगो विशेषकर कमजोर परिस्थितियों में रहने वालों लोगों के पास पर्याप्त पौष्टिक भोजन की उपलब्ता सुनिश्चित करते हुये वर्ष 2030 तक भुखमरी एवं कुपोषण को समाप्त करना है। इसका उद्देश्य आमजन केन्द्रित ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा के साथ वर्ष 2030 तक कृषि उत्पादकता व आय को दोगुनी करना भी है। सतत् कृषि को बढ़ावा देना, छोटे

किसानों का समर्थन करना तथा भू–प्रौद्योगिकी व बाजारों तक समान पहुँच बनाने जैसे उपाय भुखमरी एवं गरीबी के उन्मूलन के लिये आधारभूत है। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु बुनियादी ढांचे एवं प्रौद्योगिकी में निवेश सुनिश्चित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है।

लक्ष्य–3: आरोग्य एवं कल्याण- एस.डी.जी.–3 का उद्देश्य सभी अवस्थाओं में स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना एवं आरोग्य को बढ़ावा देना है जो कि सतत् विकास के लिये महत्वपूर्ण है। एस.डी.जी.–3 सभी प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के निवारण पर केन्द्रित है, जिनमें संक्रामक, असंक्रामक एवं पर्यावरणीय रोग, प्रजनन, मातृ व शिशु स्वास्थ्य, युनिवर्सल हेल्थ कवरेज तथा सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण व किफायती दवाओं एवं टीकों तक पहुँच सम्मिलित है। एस.डी.जी.–3 के प्रयास बाल मृत्यु दर को कम करने, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने तथा HIV/,ML, तपेदिक, मलेरिया व अन्य रोगों से निपटने की दिशा में है।

लक्ष्य–4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा- सतत विकास लक्ष्य–4 का उद्देश्य सभी के लिये समावेशी व समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा जीवनभर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है जो कि लोगो के जीवन व सतत् विकास के लिये मूलभूत है। इस लक्ष्य का उद्देश्य सभी लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण करना है तथा सभी के लिये गुणवत्तापूर्ण तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा तक समान पहुँच के अवसर सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य किफायती व्यवसायिक प्रशिक्षण तक समान पहुँच उपलब्ध करवाना, लैंगिक एवं धन संबंधी असमानताओं को समाप्त करना तथा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच को प्राप्त करना भी है।

लक्ष्य–5: लैंगिक समानता- एस.डी.जी.–5 का उद्देश्य महिलाओं एवं लड़कियों के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों का हर जगह से अंत सुनिश्चित करना है। महिलाओं एवं लड़कियों के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों का अंत करना न केवल मूलभूत मौलिक अधिकार है बल्कि समाजों के सतत्/स्थायी भविष्य के लिये भी महत्वपूर्ण है। महिलाओं एवं लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सम्मानजनक कार्य और राजनीति व आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व के समान अवसर प्रदान कर स्थायी अर्थव्यवस्था को प्राप्त किया जा सकेगा और वृहद रूप में समुदायों व मानवता को लाभ होगा। महिलाओं को भूमि व सम्पति, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रौद्योगिकी व इंटरनेट पर

समान अधिकार देना महत्वपूर्ण है। आज सरकारी कार्यालयों में पहले से अधिक महिलाएं हैं जो कि लैंगिक समानता को अर्जित करने में सहायक होगी।

लक्ष्य–6: शुद्ध जल एवं स्वच्छता- लक्ष्य–6 सभी के लिये जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंध सुनिश्चित करने के लिये प्रयास करता है तथा वैश्विक राजनीति के क्षेत्र में इनके प्रति बढ़ते ध्यान को दर्शाता है। शुद्ध पानी एवं स्वच्छता लोगों को रोगों से बचाती है तथा उन्हें आर्थिक रूप से ओर अधिक मजबूत बनाती है। जल का अभाव व जल की खराब गुणवत्ता विश्वभर में कम आय वाले परिवारों की खाद्य सुरक्षा, आजीविका के विकल्पों तथा शिक्षा के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। एजेण्डा 2030 मानता है कि ताजा जल के स्त्रोतों व पारिस्थितिकी तंत्रों के सतत् प्रबंधन पर सामाजिक विकास व आर्थिक समृद्धता निर्भर है।

लक्ष्य–7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा- एस.डी.जी.–7 का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, नवीनीकरणीय स्त्रोतों के उपयोग में वृद्धि करना तथा सभी के लिये सतत् व आधुनिक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। विकास के इंजन को इंधन देने में ऊर्जा का योगदान केन्द्रीय है तथा समाजों के विकास में इसकी भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता है। यह विश्व की प्रत्येक प्रमुख चुनौतियों व अवसरों के केन्द्र में है जो या तो व्यवसाय को प्रारम्भ करने या खाद्यान उत्पादन या आय बढ़ाने से संबंधित है। सतत् ऊर्जा एक अवसर है जो जीवन, अर्थव्यवस्था एवं पृथ्वी को बदल सकता है।

लक्ष्य–8: सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास- सतत विकास लक्ष्य 8 उत्पादकता के उच्च स्तर को अर्जित करके और प्रौद्योगिकी नवाचारों के माध्यम से सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर कंन्द्रित हैं। उद्यमिता व रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों को बढ़ावा देना इस लक्ष्य की कुंजी है जैसे कि बधुआ मजदूरी, दासता एवं मानव तस्करी के उन्मूलन हेतु प्रभावी उपाय करना। इस लक्ष्य में वर्ष 2030 तक पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार और सम्मानजनक कार्य को अर्जित करना, अनौपचारिक रोजगार एवं लिंगात्मक वेतन भेद को कम करना तथा सभी महिलाओं एवं पुरुषो के लिये सुरक्षित एवं संरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना सम्मिलित है।

लक्ष्य–9: उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना- लक्ष्य 9 का उद्देश्य लचीले आधारभूत ढांचे का निर्माण करने, समावेशी एवं सतत औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने तथा नवाचारों

का बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य में सतत् विकास के तीन महत्वपूर्ण पहलू बुनियादी ढांचा, औद्योगिकीकरण एवं नवाचार सम्मिलित है। यह गोल गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ एवं लचीला आधारभुत ढांचा विकसित करने, आर्थिक विकास एवं मानव कल्याण को समर्थन देने, सभी के लिये किफायती एवं समान उपलब्धता पर ध्यान में रखकर सतत् व लचीले अवसंरचनागत विकास मे सहयोग करने तथा कई टार्गेट्स के साथ समावेशी एवं संधारणीय औद्योगीकीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। कई देशों के सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिये परिवहन, सिंचाई, ऊर्जा सहित अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश करना महत्वपूर्ण है।

लक्ष्य–10: असमानताओं में कमी लाना- लक्ष्य–10 राष्ट्रों में उनके भीतर एवं उनके मध्य असमानता में कमी लाने पर केन्द्रित है। एस.डी.जी. 10 का उद्देश्य उम्र, लैंगिक, दिव्यांगता, धर्म एवं अन्य स्थिति के आधार पर देश के अन्दर के साथ–साथ देशो के मध्य आय की असमानताओं को कम करना है। आय एवं धन की असमानताएं गंभीर है तथा विश्वभर में फैली हुई है। असमानता न केवल प्रगति में बाधक है बल्कि लोगों को अवसरों से वंचित करती है और अंततः अत्यधिक गरीबी की स्थिति की ओर ले जाती है।

लक्ष्य–11: संधारणीय शहर एवं समुदाय- एस.डी.जी. 11 शहरों पर केन्द्रित है क्योंकि विश्व की आधी से ज्यादा आबादी उनमें रहती है। इस लक्ष्य का उद्देश्य शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला एवं संवहनीय बनाना है। शहरीकरण के परिणामस्वरूप नयी नौकरियों एवं अवसरों का सृजन हुआ है एवं गरीबी में कमी आई है। शहरों का सतत् विकास राष्ट्रो के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समृद्ध होने के अवसर प्रदान करता है। संसाधनों के उपयोग में सुधार तथा प्रदूषण व गरीबी को कम करने पर ध्यान केन्द्रित कर नगरीय क्षेत्र की तेजी से विकास करने की चुनौतियों को दूर किया जा सकता है जिसमें आधारभुत सुविधाओं, ऊर्जा, आवास की उपलब्धता तथा ग्रीन हाऊस गैसो के उत्सर्जन को कम करने के प्रावधान सम्मिलित है।

लक्ष्य–12: उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन- लक्ष्य 12 का उद्देश्य उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन प्रतिमान सुनिश्चित करना है। यह गोल प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग, ऊर्जा दक्षता व टिकाऊ आधारभूत संरचना को बढावा देने तथा सभी की बुनियादी सेवाओं

तक पहुँच, हरित व सम्मानजनक कार्य एवं एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने पर केन्द्रित है। यह लक्ष्य लोगो में जागरूकता उत्पन्न कर एवं शिक्षा के माध्यम से सतत् उपभोग एवं अपशिष्ट कम करने को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह गोल विशेष नीतियों एवं पर्यावरण के लिये हानिकारक पदार्थों के पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन के नवीन वैश्विक अनुबंधों सहित विभिन्न उपायो के माध्यम से और अधिक सतत उपभोग एवं उत्पादन प्रतिमानों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

लक्ष्य—13: जलवायु कार्रवाई- लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्यवाही करने का आह्वान करता है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभरा है क्योंकि दुनिया बढ़ते समुद्रीय स्तर, विषम चरम मौसम परिस्थितियों एवं ग्रीन हाऊस गैसों की बढ़ती सांद्रता का सामना कर रही है जो सनी के जीवन विशेषकर तटीय क्षेत्रो में रह रही आबादी के लिये खतरा है। ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिये वित्त की उपलब्धता व क्षमताओं को मजबूत करने सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने व अनुकूलन से संबंधित महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है। यह लक्ष्य जलवायु से संबंधित खतरों के लिये लचीलेपन एवं अनुकूलन क्षमता के निर्माण करने तथा राष्ट्रीय नीतियों में ऐसे उपायो को एकीकृत करने के बारे में कहता है। यह न केवल प्रभावी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली को स्थापित करने पर बल्कि प्रभावों को कम करने पर केन्द्रित है। यह इन्हीं कारणो से राष्ट्रो के मध्य साझेदारी एवं प्रतिबद्धता की भूमिका पर जोर देता है।

लक्ष्य—14: जल में जीवन- सतत् विकास लक्ष्य 14 का उद्देश्य सतत विकास हेतु महासागरों समुद्रों व सागरीय संसाधनो का संरक्षण एवं सतत् उपयोग करना है। एस.डी.जी. 14 जलीय जीवन के सामने आ रही चुनौतियों में से कुछ समुद्री पोषक तत्वों के प्रदूषण व संसाधनो में कमी, जैव विविधता के क्षरण व हानि, माहसागरों के अम्लीकरण जिन सभी का प्राथमिक कारण मानव व्यवहार हैं का समाधान करना चाहता हैं। इस गोल में सुधारात्मक मानवीय उपायों से संबंधित लक्ष्य रखे गये है जिनमें उत्पादन य अधि मत्स्याटन को प्रभावी ढंग से विनियमित करना, समुद्र एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना, महासागरों के स्वास्थ्य में सुधार करने से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने तथा लघु स्तरीय मछुआरों आध की समुद्री संसाधनो एवं बाजारों तक पहुँच प्रदान करना सम्मिलित है।

चित्र–4: 17 सतत विकास लक्ष्य के सारांश

लक्ष्य–1– गरीबी का अंत

हर जगह से सभी रूपों में गरीबी ख़त्म करना

लक्ष्य–2– भुखमरी समाप्त करना

भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और सतत् कृषि को बढ़ावा देना

लक्ष्य–3– आरोग्य एवं कल्याण

स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना

लक्ष्य–4– गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना

लक्ष्य–5– लैंगिक समानता

लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना

लक्ष्य–6– शुद्ध जल एवं स्वच्छता

सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना

लक्ष्य–7– किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा

सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, आधुनिक और सतत् ऊर्जा की प्राप्ति सुनिश्चित करना

लक्ष्य–8– सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास

सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार और शालीन काम को बढ़ावा देना

लक्ष्य–9– उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना

बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना

Image Source: SPSP (2024), UNICEF-Raipur, Chhattisgarh

लक्ष्य–10– असमानताओं में कमी लाना

देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता को कम करना

लक्ष्य–11– संधारणीय शहर एवं समुदाय

शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना

लक्ष्य–12– उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन

सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना

लक्ष्य–13– जलवायु कार्रवाई

जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना

लक्ष्य–14– जल में जीवन

सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना

लक्ष्य–15– भूमि पर जीवन

स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा, पुनर्स्थापना और स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना, जंगलों का स्थायी प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण से निपटना, भूमि क्षरण को रोकना और उलटना, और जैव विविधता के नुकसान को रोकना

लक्ष्य–16– शांति, न्याय एवं सुदृढ संस्थाएंन

सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना।

लक्ष्य–17– लक्ष्यों के लिये भागीदारीयां

कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना

लक्ष्य–15: भूमि पर जीवन- एस.डी.जी. 15 का उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करना, पुनःस्थापित करना व सतत् उपयोग करना, सभी प्रकार के सीमंकित व गैर सीमंकित, मनबनिर्मित व माइक्रोक्लाइमेट संबंधित वनों का स्थायी प्रबंध करना, मरूस्थलीकरण को रोकना एवं भूमि तथा बिगड़े बनो का क्षरण को रोकना व पुनर्स्थापित करना तथा जैव विविधता की हानियों को रोकना है जो कि हमेशा पर्यावरण से संबंधित नीतियों के निर्माण से संबंधित विचार–विमर्शो के दौरान केन्द्र में रहे हैं। वन एवं आर्दभूमि सहित स्थलीय पारिस्थतिकी तंत्र सभी को उपयोगी बाँस, इमारती लकड़ी, निर्माण व ऊर्जा हेतु कच्चा माल तथा भोजन जैसी वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं की एक श्रंखला है जिनमें मिट्टी की गुणवत्ता बनाये रखना, जैव विविधता हेतु आवासों का प्रावधान, जल गुणवत्ता को बनाये रखने के साथ–साथ जल–प्रवाह के नियमन व कटाव नियंत्रण शामिल है जो कि स्थल पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाती है। गोल 15 इस पर भी प्रकाश डालता है कि किस प्रकार ये तंत्र बाढ़ व भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की जोखिमो कम करने में योगदान करता है तथा जलवायु को नियंत्रित करते हुये कृषि तंत्र की उत्पादकता को बनाये रखता है। इसके अलावा यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, पुनःस्थापना एवं बढ़ावा देने के लिये ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल देता है।

लक्ष्य–16: शांति, न्याय एवं सुदृढ संस्थाएं- एस.डी.जी. 16 सतत विकास के लिये शांतिपूर्ण एवं समावेशी समुदायों को बढ़ावा देने, सभी की न्याय तक पहुँच प्रदान करने तथा सभी स्तरों पर प्रभावी, जिम्मेदार एवं समावेशी संस्थानों के निर्माण करने की मांग करता है। शांति, न्याय तथा प्रभावी, उत्तरदायी एवं समावेशी संस्थान सतत् विकास के केन्द्र में हैं। विकास, वृद्धि एवं समाज के कल्याण के लिये हिंसा एवं सशस्त्र संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण व विनाशकारी चुनौतियों है। वर्ष 2030 के वैश्विक सतत् विकास एजेण्डा पारदर्शी व प्रभावी स्थानीय शासन एवं न्यायिक प्रणाली को बढ़ावा देने, अपराध एवं यौन व लैंगिक आधारित हिंसा को कम करने, मानव हत्या व तस्करी के मामलों से निपटने तथा बाल अधिकारों से संबंधित हिसांओ का अंत करने का आह्वान करता है। यह सभी व्यक्तिगत, रिश्तेदारी, सामुदायिक एवं सामाजिक स्तरों पर हिंसा से संबंधित चुनौतियों के सामाधान करने की मांग करता है।

लक्ष्य–17: लक्ष्यों के लिये भागीदारीयां- गोल 17 सभी सतत विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह गोल सतत विकास के लिये क्रियान्वयन के साधनों को सुदृढ करने तथा वैश्विक साझेदारियों को पुनर्जीवित करने की मांग करता है। यह सभी स्तरों पर लोगों एवं पृथ्वी को केन्द्र में रखने वाले सिद्धान्तों एवं मूल्यों, साझा विजन तथा साझा लक्ष्यों पर निर्मित समावेशी साझेदारियों को बढ़ावा देता है।

17.3–सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

भारत भी विश्व के साथ–साथ 'कार्रवाई दशक' के पथ पर आगे बढ़ा है। इस कार्रवाई दशक में एजेण्डा 2030 को आगे बढ़ाने राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग द्वारा देश में एस.डी.जी. के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण किया जा रहा है। नीति आयोग एजेण्डा 2030 को आगे ले जाने के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जो कि सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की भावना है। यह एस.डी.जी. को आत्मसात, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करने के अभियान में केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठनों जैसे यू.एन. सिस्टम, थिंक टैंक व नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। नीति आयोग का लक्ष्य न केवल एस.डी.जी. पर आवधिक समंको का संकलन करना ही नहीं है बल्कि लक्ष्यों एवं टार्गेट्स को न केवल मात्रात्मक रूप से अर्जित करने के कार्य में बल्कि गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाये रखने में भी सक्रिय रूप से कार्य करता है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) को राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) को विकसित करने का उत्तरादायित्व सौंपा गया है जो एस.डी.जी. एवं संबद्ध टार्गेट्स की प्रगति की मॉनिटरिंग करने में सहायता करता हैं। राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के सांख्यिकीय संकेतक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर एस.डी.जी. की मॉनिटरिंग करने के मुख्य आधार है तथा विभिन्न एस.डी.जी. के अन्तर्गत टार्गेट्स को अर्जित करने की नीतियों के परिणामों को वैज्ञानिक रूप से मापते हैं। इस क्रम में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क बनाया गया है तथा यू.एन. इंडिया के सहयोग से

राष्ट्रीय एस.डी. जी. डेशबोर्ड भी तैयार किया है। एन.आई.एफ. के एस.डी.जी. संकेतको की समीक्षा की एक अनवरत प्रक्रिया है तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अन्य हितधारकों के साथ विचार–विमर्श कर वर्तमान संकेतको की उपयुक्तता के साथ–साथ प्रासंगिक लक्ष्यों के लिये नये संकेतको का परीक्षण करता रहता है। वर्तमान में एस.डी.जी. पर हुई प्रगति को मापने के लिये एन.आई.एफ. में 286 संकेतक और 169 वैश्विक टारगेट सम्मिलित है।

17.4 एसडीजी इंडिया इंडेक्स एसडीजी इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए नीति आयोग द्वारा विकसित एक टूल है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स का उद्देश्य नीति निर्माताओं को उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है जिन पर ध्यान और संसाधनों की आवश्यकता है, और एसडीजी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। यह एसडीजी हासिल करने की दिशा में समग्र रूप से देश की प्रगति की निगरानी करने में भी मदद करता है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स 1.0, दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। जिसमे सूचकांक की गणना 62 संकेतकों का उपयोग करके की गई थी। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2.0 सूचकांक का दूसरा संस्करण है, जिसे दिसंबर 2019 में जारी किया गया था। इसे 100 संकेतकों का उपयोग करके बनाया गया है, जिसमे 16 एसडीजी लक्ष्यों (लक्ष्य 17 को छोड़कर) में 54 टारगेट को शामिल किया गया था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 सूचकांक का नवीनतम संस्करण है जिसे 2021 में लॉन्च किया गया है। इसका गणना 109 संकेतकों का उपयोग करके किया गया है जो 16 लक्ष्यों में से 70 लक्ष्यों को कवर करते हैं।

चित्र–0: एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 (2021) मे राज्यो की स्थिति

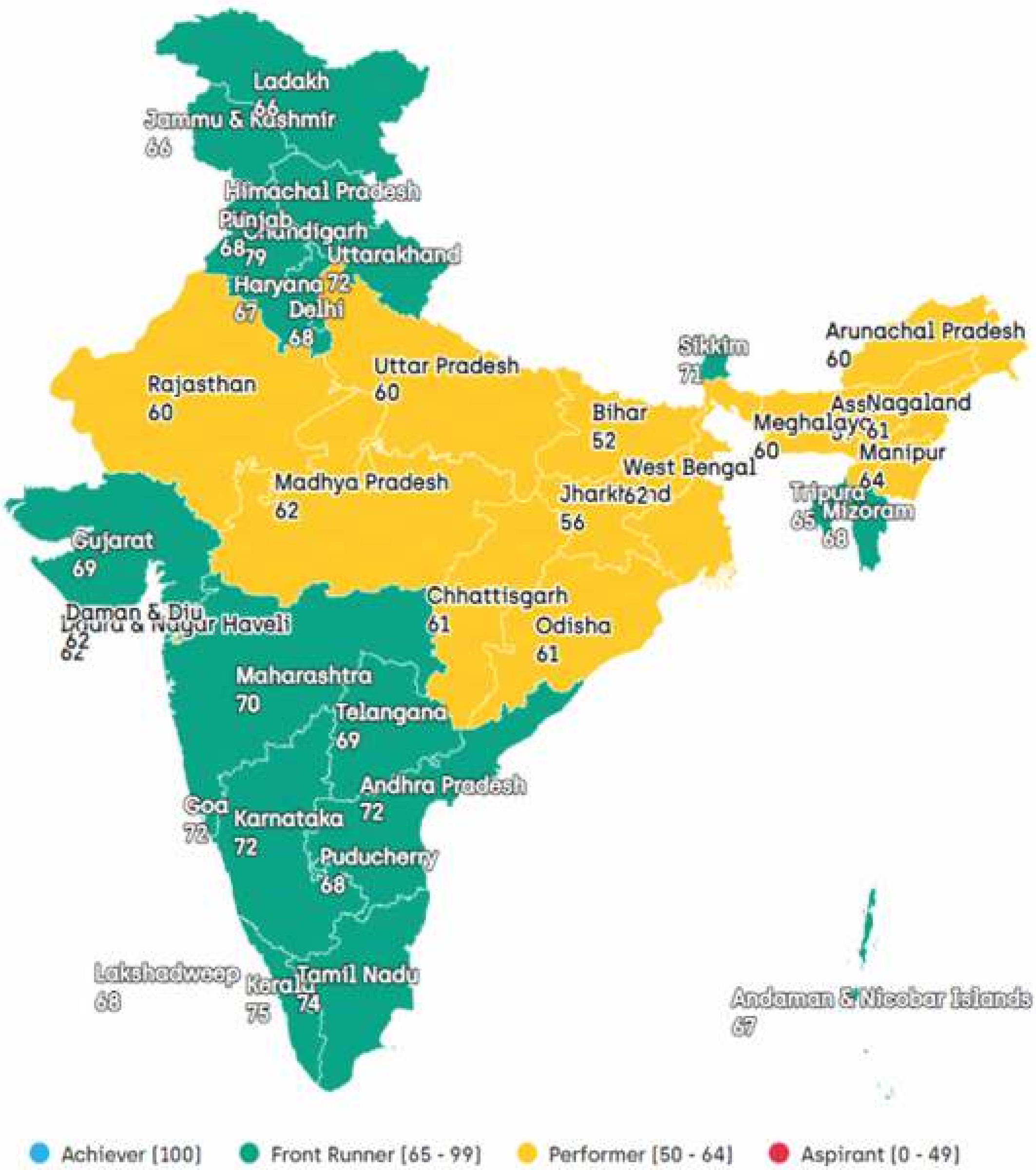

स्रोत- नीति आयोग एस डी जी डॅशबोर्डए भारत सरकार

एस. डी. जी. इंडिया इंडेक्स में, प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के समग्र स्कोर की गणना प्रत्येक गोल में उनके प्रदर्शन के औसत के आधार पर की गई है। समग्र स्कोर की सीमा 0 से 100 है जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की गोल्स के अन्तर्गत टार्गेट्स को प्राप्त करने की उनकी समग्र उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है । राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों, अचीवर (Achiever) इंडेक्स स्कोर 100 के बराबर, फ्रंट – रनर (Front Runner) इंडेक्स स्कोर 65–99, परफॉर्मर (Performer) इंडेक्स स्कोर 50–64 एवं एस्पिरेंट (Aspirant) इंडेक्स स्कोर 50 से कम में वर्गीकृत किया गया है।

- एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में, 28 में से 15 राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में थे और 13 राज्य परफॉर्मर श्रेणी में थे, केंद्र शासित प्रदेशों में से 1 को परफॉर्मर और 7 को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया था।

- राज्यों के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 स्कोर 52 और 75 के बीच है; केंद्रशासित प्रदेशों के लिए यह 62 से 79 बैंड के अंतर्गत आता है। यह 2019–20 से एक उल्लेखनीय सुधार प्रस्तुत करता है, जब राज्यों के लिए स्कोर 50 और 70 और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 59 और 70 के बीच था।

- केरल ने 75 के स्कोर के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। चंडीगढ़ ने भी 79 के स्कोर के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा।

- तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर रहे जबकि गोवा, उत्तराखंड, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश संयुक्त रूप से तालिका में चौथे स्थान पर रहे।

- भारत के समग्र स्कोर में सुधार हुआ, जो 2019–20 में 60 से बढ़कर 2020–21 में 66 हो गया। इससे पता चलता है कि कुल मिलाकर देश एसडीजी हासिल करने की दिशा में अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुका है।

- सभी राज्यों ने 1 से 12 अंकों के बीच अपने स्कोर में सुधार किया है। 2019 से स्कोर में सुधार के मामले में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड क्रमशः 12, 10 और 8 अंकों की वृद्धि के साथ 2020–21 में शीर्ष पर रहे।

17.4.1 एसडीजी इंडिया इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन

- एसडीजी इंडिया इंडेक्स–2021 में छत्तीसगढ़ का समग्र स्कोर 61 अंक था और वें 28 राज्य में 19वें स्थान पर था। छत्तीसगढ़ का स्थान परफॉर्मर श्रेणी में था और एसडीजी लक्ष्य–5 में शीर्ष स्थान पर था।

- 2019–21 के दौरान राज्य के स्कोर में 5 अंक का सुधार हुआ हे। राज्य की रैंक भी 2 पायदान बढ़ी, 2019 में राज्य की रैंक 28 राज्यों में 21 थी।

- 2019–21 के दौरान – एसडीजी लक्ष्य–2, लक्ष्य–3, लक्ष्य–4, लक्ष्य–5, लक्ष्य–7, लक्ष्य–10, लक्ष्य–11, लक्ष्य–12 और लक्ष्य–13 सकारात्मक रूप से आगे बढ़े ।

- वर्तमान मे सरकार को चार एसडीजी लक्ष्यों– लक्ष्य–1, लक्ष्य–2, लक्ष्य–9, और लक्ष्य–13 पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमे समग्र राज्य स्कोर 50 से नीचे है।

- पाँच एसडीजी लक्ष्यों– लक्ष्य–3, लक्ष्य–4, लक्ष्य–5, लक्ष्य–8, और लक्ष्य–13 में, समग्र राज्य स्कोर 50 और 64 के बीच है, जो आने वाले वर्षों में सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण सुधार की गुंजाइश को दर्शाता है।

तालिका 1: एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति को दर्शाने वाली सारणी

एसडीजी लक्ष्य	2018 (1.0)		2019-20 (2.0)		2020-21 (3.0)	
	छत्तीसगढ़	भारत	छत्तीसगढ़	भारत	छत्तीसगढ़	भारत
लक्ष्य 1	50	54	49	50	49	60
लक्ष्य 2	45	48	27	35	37	47
लक्ष्य 3	42	52	52	61	60	74
लक्ष्य 4	53	58	52	58	55	57
लक्ष्य 5	49	36	43	42	64	48
लक्ष्य 6	98	63	92	88	89	83
लक्ष्य 7	35	51	56	70	78	92
लक्ष्य 8	56	65	67	64	64	61
लक्ष्य 9	30	44	38	65	36	55
लक्ष्य 10	73	71	60	64	72	67
लक्ष्य 11	54	39	49	53	78	79
लक्ष्य 12	-	-	58	55	64	74
लक्ष्य 13	-	-	29	60	38	54
लक्ष्य 15	100	90	97	66	65	66
लक्ष्य 16	65	71	71	72	71	74
कंपांज़िट स्कोर	58	57	56	60	61	66
संकेतकों की संख्या	62		100		109	
लक्ष्य की संख्या	39		54		70	

स्रोतः एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट (2018–2021), नीति आयोग, भारत सरकार

- 6 एसडीजी लक्ष्यों– लक्ष्य –6, लक्ष्य –7, लक्ष्य–10, लक्ष्य–11, लक्ष्य–15 और लक्ष्य–16 में छत्तीसगढ़ को फ्रंट रनर श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ था।
- पांच एसडीजी लक्ष्यों– लक्ष्य–3, लक्ष्य–4, लक्ष्य–5, लक्ष्य–8 और लक्ष्य–12 में छत्तीसगढ़ को परफॉर्मर श्रेणी में में स्थान प्राप्त हुआ था।
- चार एसडीजी लक्ष्यों – लक्ष्य–1, लक्ष्य–2, लक्ष्य–9 एवं लक्ष्य–13 में राज्य को आकांक्षी श्रेणी में में स्थान प्राप्त हुआ था।
- पांच एसडीजी लक्ष्यों में सबसे बड़ी छलांग देखी गई– लक्ष्य–2 (+10), लक्ष्य–5 (+21), लक्ष्य–7 (+22), लक्ष्य–10 (+12), लक्ष्य–11 (+29)।

17.5 सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति छत्तीसगढ़ की प्रतिबद्धता

राज्य के समग्र विकास के लिये राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है एवं वर्ष 2030 तक एस. डी. जी. को अर्जित करने के अपने प्रयासों को गति प्रदान की गई है। राज्य में एस. डी. जी. के क्रियान्वयन के संदर्भ में सम्पादित की गई कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्न प्रकार हैं।

17.5.1 संस्थागत व्यवस्था

छत्तीसगढ़ सरकार ने एसडीजी की समीक्षा और निगरानी की ज़िम्मेदारी राज्य योजना आयोग (SPC) को सौंपी है। एसडीजी की प्रगति के सुचारू कार्यान्वयन और निगरानी के लिए, राज्य सरकार ने 23 जनवरी 2021 को राज्य योजना आयोग के नेतृत्व में तीन समितियों का गठन किया है। तीन समितियां हैं– (1) माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एसडीजी (State Level Steering Committee-SLSC) पर राज्य स्तरीय संचालन समिति, (2) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसडीजी पर राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (State Level Implementation and Monitoring Committee-SLIMC), और (3) एसडीजी कार्यान्वयन की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने और निगरानी के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एसडीजी पर जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (District Level Implementation and Monitoring Committee-DLIMC।

चित्र–6: एसडीजी निगरानी के लिए संस्थागत व्यवस्था

IV.5.2 छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला संकेतक ढांचा Chhattisgarh State and District Indicators Framework SIF and DIF) का निर्माण

- छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला संकेतक ढांचा को प्रस्तुत करने के पहले 'छत्तीसगढ़ का एसडीजी विजन 2030' रिपोर्ट भी प्रकाशित किया है, जिसमे सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिए राज्य की दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें 2024 तक की 7–वर्षीय रणनीतियों और 2020 तक की तीन–वर्षीय कार्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है।
- छत्तीसगढ़ में एसडीजी की प्रगति की निगरानी के महत्व और इसके लिए विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता को समझते हुए, राज्य योजना आयोग ने वैश्विक संकेतक ढांचा और राष्ट्रीय संकेतक ढांचा के आधार पर 2021 मे (1) छत्तीसगढ़–राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (SIF), और 2022 मे (2) छत्तीसगढ़–जिला संकेतक ढांचा (DIF) विकसित किया ।
- छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला संकेतक ढांचा को प्रस्तुत करने हेतु राज्य योजना आयोग के नेतृत्व मे सतत विकास संबंधित राज्य की विभिन्न विभागों, नीति आयोग (NITI Aayog) की प्रतिनिधियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (UN Organisations) मुलतः यूनिसेफ (UNICEF) और अन्य हितधारकों के साथ भी उचित परामर्श किए गये है।

17.5.3 छत्तीसगढ़–एसआईएफ तैयार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया

○ वर्ष 2021 मे, छत्तीसगढ़ मे राज्य योजना आयोग के नेतृत्व मे और UNICEF छत्तीसगढ़ के तकनीकी सहायता से छत्तीसगढ़ एसआईएफ को प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ – एसआईएफ तैयार करने के लिए सहभागी परामर्श प्रक्रिया राज्य योजना आयोग के नेतृत्व मे कई चरणों द्वारा संचालित की गई है जो इस प्रकार हैं–

- छत्तीसगढ़ – एसआईएफ तैयार करने के पहले चरण मे एसडीजी से संबंधित राज्य के विभागों की पहचान की गई है और सीजी–एसआईएफ की तैयारी में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा नोडल अधिकारी नामित किए गए।
- दूसरे चरण मे 11 समूहों की गठन की गई और जिसके परामर्श से छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं और एसडीजी लक्ष्यों के साथ मैप किया गया।
- तदनुसार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एसडीजी संकेतक ढांचे के विकास के लिए डवैच्‍ के द्वारा जारी किए गये दिशानिर्देशों का पालन करते हुए प्रमुख हितधारकों (विभिन्न विभागों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों) के साथ कई परामर्शी कार्यशालाएं (16 अक्टूबर 2020 से 04 नवंबर 2020 के दौरान) आयोजित की गई हैं।
- एनआईएफ, और नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किए गये एसडीजी इंडिया संकेतकों के साथ एसआईएफ को संरेखित करने की समीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए नीति आयोग के प्रतिनिधियों सहित संबंधित विभागों के सचिवों की भागीदारी के साथ 17 नवंबर 2020 को राज्य योजना आयोग में एक राज्य स्तरीय बैठक के पश्चात 2021 मे छत्तीसगढ़–एसआईएफ तैयार की गई है।

17.5.4 छत्तीसगढ़ –एसआईएफ की मुख्य विशेषताएं

- छत्तीसगढ़ –एसआईएफ में 17 सतत विकास लक्ष्य मे 16 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी लक्ष्य–14 को छोड़कर) के प्रगति को मापने के लिए कुल 275 संकेतक शामिल हैं।

- 275 संकेतकों में से 231 एनआईएफ से हैं, जिनमें से 217 संकेतक सीधे एनआईएफ से लिए गए हैं और 14 संकेतक संशोधन के बाद एनआईएफ से शामिल किए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, 44 नए संकेतक शामिल किए गए जो नीति आयोग की एसडीजी संकेतक सूची के साथ संरेखित हैं।
- संकेतकों को छत्तीसगढ़ सरकार के संबंधित विभागों और डेटा स्रोत के साथ मैप किया गया हैं।
- एसडीजी संकेतकों को केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम से भी मैप किए गए।

17.5.5 छत्तीसगढ़ –डीआईएफ तैयार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया

वर्ष 2022 मे, छत्तीसगढ़ मे राज्य योजना आयोग के नेतृत्व मे और UNICEF छत्तीसगढ़ के तकनीकी सहायता से छत्तीसगढ़ डीआईएफ को प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ – डीआईएफ तैयार करने के लिए सहभागी परामर्श प्रक्रिया राज्य योजना आयोग के नेतृत्व मे कई चरणों द्वारा संचालित की गई है जो इस प्रकार हैं–

- छत्तीसगढ़ – डीआईएफ तैयार करने के पहले चरण मे एसडीजी से संबंधित राज्य के विभागों की पहचान की गई है और छत्तीसगढ़ –डीआईएफ की तैयारी में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
- दूसरे चरण मे स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए, छत्तीसगढ़ –डीआईएफ पर विचार करते हुए जिला अधिकारियों के साथ–साथ राज्य के संबंधित विभागों के साथ कई दौर की परामर्शी कार्यशालाएं और बैठकें आयोजित की गई हैं।
- कार्यशाला की व्यवस्था करने से पहले, छत्तीसगढ़ सरकार के 23 राज्य विभागों की मैपिंग की गई जो सीजी–डीआईएफ की तैयारी के लिए डेटा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। तदनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की प्रमुख भागीदारी के साथ परामर्शी कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर संकेतकों, प्रत्येक संकेतक के डेटा स्रोतों और डेटा अंतराल और लक्ष्यवार योजनाओं/कार्यक्रम पर चर्चा की गई।

- ये कार्यशालाएँ प्रत्येक संबंधित विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित की गईं और छत्तीसगढ़ –एसआईएफ के साथ संरेखित संभावित संकेतकों की सूची की पहचान करते हुए एक मसौदा छत्तीसगढ़ –डीआईएफ तैयार किया गया।
- छत्तीसगढ़ –डीआईएफ की मसौदा सूची पर उनके मूल्यवान और सुझावों पर चर्चा करने के लिए जिला अधिकारियों (कलेक्टरों, सीईओ जिला पंचायत और डीपीएसओ) के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी।
- जिला अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक/सुझावों पर चर्चा करने और जिला संकेतक ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभागों के एसडीजी नोडल अधिकारियों के साथ एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई।
- अंत में, राज्य योजना आयोग ने राज्य के विभागों के नोडल अधिकारियों और जिलों के अधिकारियों के सभी फीडबैक/सुझावों पर विचार करते हुए 82 संकेतकों की पहचान करते हुए छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (छत्तीसगढ़ –डीआईएफ) तैयार किया है। छत्तीसगढ़ –डीआईएफ जिला स्तर पर एसडीजी की दिशा में प्रगति की निगरानी की रीढ़ है। छत्तीसगढ़ –डीआईएफ यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि एसडीजी की प्रगति जिलों के साथ–साथ राज्य की अपनी सामाजिक–आर्थिक और पर्यावरणीय प्रोफ़ाइल, स्वास्थ्य प्रणाली और आर्थिक विकास के स्तर के साथ–साथ आबादी की मांगों और जरूरतों को भी दर्शाती है।

17.5.6 छत्तीसगढ़ –डीआईएफ की मुख्य विशेषताएं

- छत्तीसगढ़ –डीआईएफ जिले के अधिकारियों को यह बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है कि जिला स्तर पर सभी प्रासंगिक हितधारकों को शामिल करके एसडीजी को कैसे स्थानीयकृत किया जा सकता है।
- छत्तीसगढ़ –डीआईएफ में 15 एसडीजी लक्ष्य (एसडीजी लक्ष्य 14 और एसडीजी लक्ष्य 17 को छोड़कर) के लिए कुल 82 संकेतक शामिल हैं।
- कुल 45 एसडीजी टारगेट छत्तीसगढ़ –डीआईएफ द्वारा कवर किए गए हैं।

- 82 संकेतकों में से 41 परिणाम आधारित, 35 आउटपुट आधारित और 6 प्रक्रिया आधारित संकेतक हैं।
- 82 संकेतकों में से 70 संकेतकों के लिए डेटा आवधिकता वार्षिक है, 10 संकेतकों के लिए यह तीन वर्ष है, और 2 संकेतकों के लिए यह 5 वर्ष है।

तालिका 7 : छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिले के लिए बनाए गए स्टेट इर्डिकटर फ्रेमवर्क एवं डिस्ट्रीक इंडिकेटर की जानकारी वाली सारणी

एसडीजी लक्ष्य	छत्तीसगढ़ एसआईएफ चिन्हित किया गया टारगेट की संख्या	छत्तीसगढ़ एसआईएफ में संकेतकों की संख्या	छत्तीसगढ़ डीआईएफ चिन्हित किया गया टारगेट की संख्या	छत्तीसगढ़ डीआईएफ में संकेतकों की संख्या
लक्ष्य 1	7	24	2	6
लक्ष्य 2	8	21	3	7
लक्ष्य 3	13	38	6	7
लक्ष्य 4	10	20	5	9
लक्ष्य 5	9	27	5	6
लक्ष्य 6	8	14	4	10
लक्ष्य 7	5	5	1	2
लक्ष्य 8	12	31	2	5
लक्ष्य 9	8	13	2	2
लक्ष्य 10	10	9	2	3
लक्ष्य 11	10	16	3	7
लक्ष्य 12	11	16	2	6
लक्ष्य 13	5	7	2	2
लक्ष्य 14	10	0	0	0
लक्ष्य 15	12	9	2	2
लक्ष्य 16	12	21	4	8
लक्ष्य 17	19	4	0	0
कुल	169	275	45	82

स्रोत: छत्तीसगढ़ एसडीजी राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ सरकार

17.6- छत्तीसगढ़ में एसडीजी की प्रगति (राज्य एवं जिला स्तरीय)

17.6-1 पर्यवेक्षण एवं प्रकाशन

- छत्तीसगढ़ में एसडीजी की प्रगति की निगरानी दो स्तरों पर की जाती है– (1) राज्य योजना आयोग द्वारा एसआईएफ पर आधारित राज्य स्तरीय प्रगति रिपोर्ट, एवं (2) जिला स्तरीय बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट।

- यूनिसेफ **(UNICEF)** छत्तीसगढ़ ने राज्य योजना आयोग को समय समय पर एसडीजी राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय बेस लाइन और प्रगति रिपोर्ट को बनाने मे और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तकनीकी सपोर्ट प्रदान किए है।

- राज्य स्तर पर राज्य योजना आयोग ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए 2 बेस लाइन और प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। रिपोर्ट में बर्ष 2015–16 को बेस लाइन मानते हुए 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के प्रगति की डेटा को शामिल किया गया है।

- राज्य में एसडीजी के स्थानीयकरण की दिशा में, राज्य योजना आयोग ने वर्ष 2021 और 2022 मे एसडीजी जिला प्रगति रिपोर्ट के भी 2 संस्करण तैयार किए हैं।

17.6-2 एसडीजी राज्य स्तरीय बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन

- छत्तीसगढ़ राज्य एसडीजी बेसलाइन और प्रगति रिपोर्ट में 16 एसडीजी (एसडीजी 14 को छोड़कर) और 275 संकेतक शामिल हैं।

- 2021 में जारी किए गए राज्य स्तरीय बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट की पहले संस्करण में 2015–16 (बेसलाइन) के डेटा और 2018–19 और 2019–20 में प्रगति पर प्रकाश डाला गया।

- 2022 में जारी किए गए बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट की दूसरा संस्करण में 2015–16 (बेसलाइन) के डेटा और 2020–21, और 2021–22 के प्रगति पर प्रकाश डाला गया।

- नवीनतम बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट (2022) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 275 संकेतकों में से 94 ट्रैक पर हैं और 2030 तक अपनी एसडीजी लक्ष्य हासिल कर लेंगे।
- एसडीजी **लक्ष्य**–2 (भुखमरी समाप्त करना), **लक्ष्य**–3 (आरोग्य एवं कल्याण), **लक्ष्य**–5 (लैंगिक समानता) और **लक्ष्य**–8 (सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास) में विशेष ध्यान देने के ज़रूरत है।

17.6.3 एसडीजी जिला स्तरीय बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ एसडीजी जिला प्रगति रिपोर्ट में 15 एसडीजी (एसडीजी–14 और एसडीजी–17 को छोड़कर) और 82 संकेतक और 45 लक्ष्य शामिल हैं।

17.6.3.1 प्रथम संस्करण (2021) की मुख्य बातें

- छत्तीसगढ़ जिला स्तरीय बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट की पहले संस्करण (2021) में 2015–16 (बेसलाइन) के डेटा और 2020–21 में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है।
- प्रथम संस्करण में राज्य का कंपॉज़िट स्कोर 64 था।
- 2020–21 जिला स्तर के एसडीजी रॅकिंग में
  - शीर्ष पांच जिले थे– धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग और बेमेतरा
  - निचले पांच जिले थे– बस्तर, नारायणपुर, बलरामपुर, बीजापुर, और सुकमा

तालिका–3: छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय एसडीजी बेसलाइन और प्रगति रिपोर्ट 2022 में लक्ष्यवार, सूचकवार प्रगति का सारांश

एसडीजी लक्ष्य	टारगेट की संख्या	सूचक की संख्या	अपेक्षित प्रगति हुआ है ऐसे सूचक की संख्या	विशेष प्रयास की ज़रूरत है ऐसे सूचक की संख्या
लक्ष्य-1	7	24	9	15
लक्ष्य-2	7	21	3	18
लक्ष्य-3	12	38	12	26
लक्ष्य-4	8	20	12	8
लक्ष्य-5	8	27	7	20
लक्ष्य-6	6	14	11	3
लक्ष्य-7	4	5	1	4
लक्ष्य-8	11	31	8	23
लक्ष्य-9	6	13	3	10
लक्ष्य-10	3	9	3	6
लक्ष्य-11	7	16	7	9
लक्ष्य-12	7	16	10	6
लक्ष्य-13	3	7	1	6
लक्ष्य-15	6	9	2	7
लक्ष्य-16	9	21	4	17
लक्ष्य-17	2	4	1	3
कुल	106	275	94	181

स्रोत: छत्तीसगढ़ एसडीजी राज्य प्रगति रिपोर्ट 2022, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ शासन

17.6..3.1 दूसरे संस्करण (2022) की मुख्य बातें

- दूसरा संस्करण (2022) में 2015–16 (बेसलाइन) के डेटा के आधार पर 2020–21 और 2021–22 के प्रगति को दर्शाया गया है।
- 2021–2022 के दौरान छत्तीसगढ़ जिला स्तरीय कंपॉज़िट स्कोर 4 अंक बढ़कर 64 से 68 हो गया है।
- राज्य की स्थिति भी 'परफॉर्मर' (50–64) श्रेणी से 'फ्रंट रनर' (65–99) श्रेणी में आ गई है। आकांक्षी (0–49) श्रेणी में कोई भी जिला नहीं बचा है।
- जिला स्तरीय एसडीजी मे अच्छा प्रदर्शन, लक्ष्य 6 (शुद्ध जल एवं स्वच्छता), लक्ष्य 7 (किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा), लक्ष्य 12 (उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन), और लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) जहां समग्र लक्ष्य स्कोर क्रमश 81, 86, 85, और 95 हैं।
- धमतरी एसडीजी मे छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले है, और इस वर्ष 77 के एसडीजी स्कोर के साथ दोनों वर्षों (2021 – 2022) में शीर्ष पर रहा।
- 2021–22 में एसडीजी रॅंकिंग में शीर्ष पांच जिले हैं– धमतरी, बालोद, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर व निचले पांच जिले हैं– बीजापुर, बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा
- वर्ष 2022 में कुल 18 जिले 'फ्रंट रनर' श्रेणी में स्थान प्राप्त किए है; 2021–22 के दौरान 8 नए जिले परफॉर्मर से फ्रंट रनर की श्रेणी में वर्गीकृत हुए।
- 2021–22 में, 19 एसडीजी संकेतकों ने पहले ही 2030 लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, और 23 संकेतक ट्रैक पर हैं, और 40 संकेतकों पर प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत है।

तालिका–ए 4:सडीजी जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट 2022 के अनुसार जिलों के कम्पोजिट स्कोर तथा इसके आधार पर जिलो की रैंकिंग वर्ष 2020.21 एवं 2021. 22 को दर्शाने वाली सारणी

क्र.	जिला	कंपोजिट स्कोर 2020.21	रैंक	कंपोजिट स्कोर 2021.22	रैंक
1	धमतरी	75	1	77	1
2	बालोद	69	3	72	2
3	रायपुर	65	8	72	3
4	दुर्ग	67	5	70	4
5	बिलासपुर	66	6	70	5
6	राजनांदगांव	70	2	70	6
7	कांकेर	64	11	69	7
8	रायगढ़	62	17	69	8
9	महासमुंद	69	4	68	9
10	मुंगेली	63	15	68	10
11	गरियाबंद	65	7	68	11
12	बेमेतरा	65	9	67	12
13	सरगुजा	65	10	67	13
14	कोरिया	60	23	67	14
15	कबीरधाम	64	12	66	15
16	कोरबा	61	18	66	16
17	सूरजपुर	63	14	66	17
18	बलौदा बाजार	60	22	65	18
19	जांजगीर चांपा	63	13	64	19
20	नारायणपुर	58	24	64	20
21	जशपुर	62	16	63	21
22	कोण्डागांव	60	20	63	22
23	सुकमा	50	27	63	23
24	दंतेवाड़ा	60	21	63	24
25	बस्तर	61	19	62	25
26	बलरामपुर	57	25	56	26
27	बीजापुर	51	26	56	27

स्रोत : छत्तीसगढ़ एसडीजी जिला प्रगति रिपोर्ट 2022, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ शासन

मानचित्र–1 एसडीजी जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट 2022 के अनुसार जिले का स्थिति

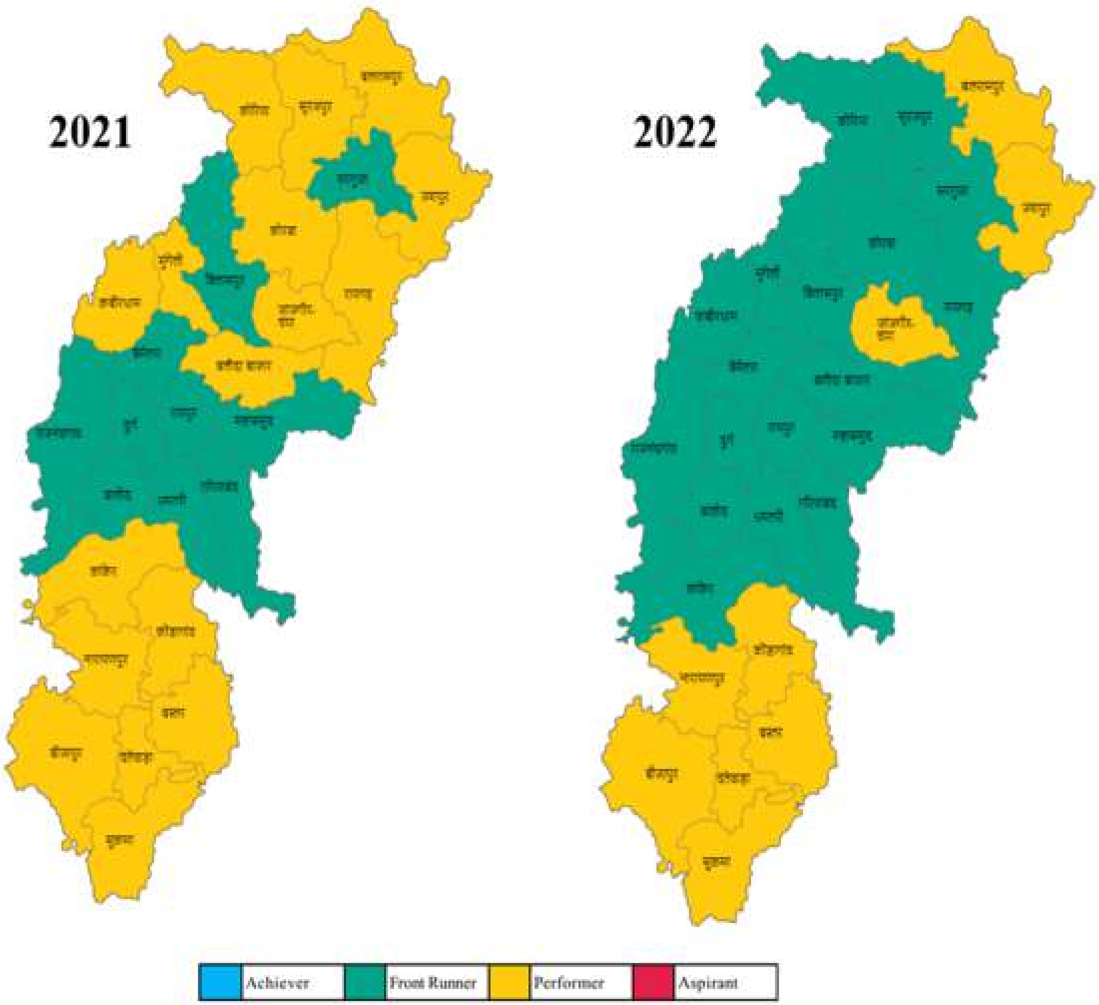

स्रोतः छत्तीसगढ़ एसडीजी डॅशबोर्ड राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ शासन

तालिका–5: एसडीजी जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट 2022 के अनुसार लक्ष्यों के सम्मुख कम्पोजिट स्कोर दर्शाते हुए शीर्ष तीन जिलों को दर्शाये जाने वाली सारणी

लक्ष्य	शीर्ष 3 जिले कंपोजिट स्कोर के साथ	लक्ष्य	शीर्ष 3 जिले कंपोजिट स्कोर के साथ
GOAL1	धमतरी (75), बिलासपुर (65), कांकेर (63)	GOAL9	दुर्ग (63), रायपुर (60), रायगढ़ (54)
GOAL2	सरगुजा (64), गरियाबंद (62), बिलासपुर (62)	GOAL10	रायगढ़ (92), दुर्ग (89), बालोद (89)
GOAL3	कबीरधाम (66), बेमेतरा (61), मुंगेली (61)	GOAL 11	बालोद (88), धमतरी (86), मुंगेली (82)
GOAL4	दुर्ग (82), बलौदाबाजार (81), जांजगीर-चांपा (81)	GOAL 12	गरियाबंद (97), बलौदाबाजार, कोरिया,बीजापुर,मुंगेली,नारायणपुर सरगुजा (96)
GOAL 5	बालोद (73), कांकेर (73), सुकमा (73)	GOAL 13	गरियाबंद (100) बालोद (99), बलौदाबाजार (99) बिलासपुर (99)
GOAL6	धमतरी (92), बालोद (90), मुंगेली (87)	GOAL15	बस्तर (100), सूरजपुर (100), कोरबा (88)
GOAL7	बस्तर (100) बिलासपुर (100), धमतरी (100), रायपुर (100)	GOAL16	दंतेवाड़ा (87), सरगुजा (82), धमतरी (81)
GOAL8	रायपुर (84), दुर्ग (64), दंतेवाड़ा (54)		

स्रोतः छत्तीसगढ़ एसडीजी जिला प्रगति रिपोर्ट 2022, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ शासन